

पर पुलों और बांधों का निर्माण करायें तथा प्रतापगढ़ जिले का विकास हो सकता है ।

(ii) REPORTED FIRING ON THE WORKERS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., HARDWAR.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Mr. Speaker, Sir, under Rule 377 I want to mention about a very serious matter on the Floor of the House and would request the hon'ble Minister to make a statement thereon.

Sir, a serious situation has arisen out of the indiscriminate firing by CISF on the workers of Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar on 23-3-1978. The CISF without any provocation attacked with firearms on the unarmed peaceful workers and killed and injured many of them including Secretaries of the CITU and AITUC unions. Within the very short period, more than 20 workers fell down with bullet injuries and hundreds were limping into blocks with major with major injuries. The fire brigade and ambulance started rushing dozens of injured and wounded to the hospital. The top management was nowhere in the scene and they were busy in holding a meeting to discuss the situation. Nearly after three hours the Executive Director, Mr. Wahi announced over intercom the withdrawal of CISF personnel and handing over the factory to the local police. Following the incident a large number of workers are being rounded up by police on various false charges. This has further worsened the situation.

Sir, I demand withdrawal and abolition of CISF and order for judicial enquiry so that culprits may be punished.

Sir, the CISF is under Home Ministry and BHEL, Hardwar is a public undertaking. Through you, Sir, I would request the concerned Ministers to make a statement on the Floor of the House as early as possible.

(iii) BOUNDARY DISPUTE BETWEEN KARNATAKA AND MAHARASHTRA.

श्री केशव राव बोडगे (नांदेड़) : दस लाख मराठी लोगों का मसला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ । कर्नाटक और महाराष्ट्र के अन्दर बेलगाम कारवार, नापानी, बालकी, सन्तपुर, औरड़, हुमानावाप आदि दस लाख मराठी लोग हैं । वहाँ

पर कर्नाटक में इन पर बहुत जुल्म हो रहा है । उन लोगों ने हर तरह से, चुनाव में तथा दूसरे तरीकों से अपने खयालात का इजहार किया है । इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद करने के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है । हमने बर्मा देश के साथ अपने बाउंडरी डिमप्यूट को हल कर लिया है, बंगला देश के साथ हल कर लिया है । लेकिन अपने ही देश में दो राज्यों के बीच जो सीमा विवाद है उस सीमा विवाद को लोकशाही के तरीकों के अनुसार हल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार अभी तक उन से कितनी और कुर्बानियां मांगती हैं, कौन सी स्ट्रगल वह चाहती है कि वे करें, कितने और उन लोगों में शहीद हों ताकि उसकी आँख खुल सके और वह इस सवाल को हल कर सके ? प्रधान मंत्री से मैं गुजारिश करूँगा कि वह इसको देखें । उनको बेलगांव के और कितने लोग शहीद चाहिये ? कब वह उनको इंसाफ दे सकेंगे ? मैं मानता हूँ कि पहले कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी का राज्य था । वह सरकार लोगों को इंसाफ नहीं देती थी । लेकिन हमने चुनाव के अन्दर लोगों से वादे किए हैं कि हम उनको इंसाफ देंगे । मैं प्रधान मंत्री से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले पर वह खामोश न बैठें रहें । लोगों के जज्बात को देखें, उनको इंसाफ दें । कई कमिशन बैठे हैं, कई चीफ मिनिस्टर तबदील हुए हैं, कई हकूमतें तबदील हुई हैं, कई प्रधान मंत्री बने हैं, इनकलाब हुआ है लेकिन इस मसले को हल नहीं किया गया है । इतना ही नहीं कर्नाटक एकीकरण समिति के छः मपांच नुमाइदे चुन कर आए हैं । उनका कहना है कि जम्हूरियत की इन बीस वाइस सालों की लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि हमारी मांग बिल्कुल जायज है । रेलवे मिनिस्टर साहब प्रो० दंडवते ने फरमाया था कि जनता पार्टी का राज्य हो जाएगा तो